F. No: 18015/37/2014-NM.III
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Naxal Management Division)
*****

North Block, New Delhi
Dated the 2nd April, 2014

To,

Shri Bibhuti Narayan Dubey.
Village: Sansarapur,
Post Office: Chaksunderpur Giyanpur,
Janpat Sant Ravidas Nagar,
Badohi, Uttar Pradesh – 221304.

Sub: Information sought under the Right to Information Act, 2005 – reg.

Please refer to your RTI application dated 03.03.2014 received in this Division on 25.03.2014 vide this Ministry's letter No. 18015/12/2014-NM.IV dated 25.03.2014 seeking information regarding funds released by the Central Government to the LWE affected States for the Security purpose under the RTI Act, 2005.

2. The available information with respect to point no 3 of the above mentioned RTI application is furnished as under:-

'Under the Security Related Expenditure (SRE) Scheme, the Central Government reimburses to the State Governments of 9 LWE affected States security related expenditure of 106 districts relating to ex-gratia payment to the family of civilian/security forces killed in LWE violence, insurance of police personnel, training and operational needs of security forces, compensation to Left Wing Extremist cadres who surrender in accordance with the surrender and rehabilitation policy of the concerned State Government, community policing, security related infrastructure for village defence committees and publicity material. Details of the Funds released during the year 1999-2000 to 2013-2014 under the Security Related Expenditure (SRE) Scheme for LWE affected States is enclosed as **Annexure.**'

3. Appeal u/s 19(1) of the Act, if any, is to be made within 30 days of receipt of this communication and the same in respect of this information lies with Shri M.A. Ganapathy, Joint Secretary, Naxal Management Division, Room No. 193-A/1, North Block, New Delhi – 110 001.

03 APR 2014

2/4/14
(Rambir Singh)
Director (NM) & CPIO

Encl: As above.

Copy to:

1. Shri K.S. Kusala Kumar, DS(NM) & CPIO, MHA, North Block, New Delhi w.r.t letter No: 18015/12/2014-NM.IV dated 25.03.2014.

10

Annexure

Security Related Expenditure (SRE) Scheme for LWE affected States
(Funds released during the year 1999-2000 to 2013-14)

(Figures in Rs. lakh)

State	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Andhra Pradesh	3046.00	674.00	473.82	217.35	221.00	282.00	1316.03	610.15	1079.25	582.59	227.51	2818.84	1072.77	1512.82	1798.02
Bihar	900.00	1980.00	1005.10	180.00	43.68	60.41	434.99	4.15	230.00	521.67	276.65	2941.19	1364.91	786.83	1710.89
Chhattisgarh	-	-	32.25	223.49	160.87	200.00	1085.01	967.92	1045.00	2011.64	3614.24	8774.35	4237.08	5074.01	4214.41
Jharkhand	-	-	18.80	54.00	98.07	341.27	605.85	1472.22	1724.50	2350.24	1111.10	5940.65	7535.95	6754.94	4778.74
Madhya Pradesh	500.00	141.90	69.16	82.37	139.82	23.52	108.00	251.25	170.00	399.86	10.87	155.41	27.50	65.05	55.75
Maharashtra	196.00	50.00	16.66	-	81.42	125.55	272.16	526.00	462.00	471.98	271.18	1367.17	762.91	460.44	738.51
Odisha	358.00	190.83	18.46	168.00	86.85	65.77	254.60	716.43	1216.62	1308.98	371.22	5661.61	2156.62	1531.34	4813.3
Uttar Pradesh	-	-	-	29.17	-	-	196.30	-	80.00	185.52	50.75	356.14	200.01	550.11	533.28
West Bengal	-	-	-	-	-	-	227.53	150.00	288.00	167.52	66.48	1891.08	1390.68	1330.70	2065.1
Total	**5000.00**	**3036.73**	**1634.25**	**954.38**	**831.71**	**1098.52**	**4500.47**	**4698.12**	**6295.37**	**8000.00**	**6000.00**	**29906.44**	**18748.43**	**18066.24**	**20708.00**

03 APR 2

(Rambir Singh)
Director (NM) & CPIO

27 4

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन
सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र

1496/14

RIGHT TO INFORMATION

MAR 2014 ... SECTION

आवेदक का नाम
विभूति नारायण दूबे
(आर.टी.आई. कार्यकर्ता)

निवास
ग्रा. संसारापुर, पो. चकसुन्दरपुर ज्ञानपुर
जनपद सन्त रविदास नगर, भदोही (उ.प्र.) - 221304
मो. 9450789856, 8009746719

पत्रांक - 293/F/2014 पंजीकृत दिनांक - 03 मार्च 2014

सेवा में,

URGENT RTI ACT
Diary No. 1615
& Date 07/03/14
Last Date For Disposal 12/03/14

श्रीमान् केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी महोदय
मा० प्रधानमन्त्री कार्यालय
भारत सरकार, नई दिल्ली

1- आवेदक का नाम - विभूति नारायण दूबे IPON025F004624 of ₹10/-

2- पता - उपर्युक्त उल्लिखित पता

3- अपेक्षित सूचना का विवरण - (i) सूचना की विषय-वस्तु - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक

(ii) अवधि (जिससे सूचना सम्बन्धित है) - 45 दिन

(iii) अपेक्षित सूचना का विस्तृत विवरण - आवेदक आप श्रीमान् जी से निम्नलिखित बिन्दुओं के सापेक्ष सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन करता है-

बिन्दु-1- सम्पूर्ण भारत में सन् 1980 से अब तक कुल कितने किसानों द्वारा कृषि से जुड़े उत्पाद फसलों में घाटा आने से आर्थिक रूप से तंगी हालत व बकाया ऋण की अदायगी न होने के कारण भूखमरी के कगार पर पहुँचने की स्थिति न झेल पाने के कारण आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया गया है उनका नाम, पता, आत्म-हत्या दिनांक, सरकार द्वारा सम्बन्धित किसान के आश्रितों को दी गयी आर्थिक व अन्य सहायता के सम्पूर्ण विवरण की सूची उपलब्ध कराने की कृपा करें।

A2C

बिन्दु-2 सम्पूर्ण भारत देश में सन् 1990 से अब तक कुल कितने नागरिकों व पुलिस, सी. आर. पी. एफ., भारतीय सेना, व अन्य जवानों की मृत्यु नक्सलियों के प्राणघातक हमले से हुयी है प्रत्येक के नाम, पता, मृत्यु दिनांक, सरकार द्वारा सम्बन्धित के आश्रितों

MHA MOD

[illegible]921748

क्रमशः - पृष्ठ - 2 पर

को सरकार द्वारा दी गयी आर्थिक मदद व अन्य मदद तथा ऐसे नक्सली हमले के सुरक्षा की दृष्टिकोण से अब तक की हुयी व्यवस्था के विवरण की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

MHA

बिन्दु-3. भारत सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित राज्यों को सुरक्षा व्यवस्था के मद में वर्ष 1990 से अब तक कुल कितनी धनराशि आवंटित की जा चुकी है। वर्षवार विवरण की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

MHA

Security related Expenditure

बिन्दु-4. भारत देश से सटे अन्य देशों की सीमा पर तैनात भारतीय सेना के वीर जवानों में से सन् 1990 से अब तक विदेशी आतंकवादियों व अन्य किसी भी प्रकार के हमले से अब तक कितने भारतीय सेना के वीर जवान शहीद हो चुके हैं। प्रत्येक का नाम, पता, शहीद होने का दिनांक तथा उनके आश्रितों को भारत सरकार द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी, तथा अन्य मदद के सम्पूर्ण विवरण की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

MoD

बिन्दु-5- मा० प्रधानमन्त्री जी भारत सरकार को "एक आर०टी०आई० कार्यकर्ता के रूप में अपनी सुरक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में आवेदक द्वारा लिखा गया पत्र संख्या: 81/सुरक्षा/2013 दिनांक: 26-06-2013 के सापेक्ष मा० प्रधानमन्त्री जी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? कृत कार्यवाही विवरण की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

DoP

बिन्दु-6- बिन्दु-5 में वर्णित पत्र के सन्दर्भ में आवेदक को आज दिनांक तक सुरक्षा व्यवस्था किस विधिक कारण से मुहैया नहीं करायी जा सकी है, विवरण सहित अवगत करायें। अवगत होना चाहिए कि आवेदक द्वारा "आर० टी० आई० कार्यकर्ता" के रूप में अनेक छोटे-बड़े मामलों में भ्रष्टाचार का खुलासा किये जाने से जीवन-भय अवश्यंभावी हो गया है, जिससे जिम्मेदार लोगों द्वारा कभी भी पलटवार करके हमला किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

बिन्दु-7- बिन्दु-5 में वर्णित पत्र में उल्लिखित "श्री पृथ्वीराज चव्हाण, राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय,

—— क्रमश: पृष्ठ उपर

(2)

29
6

राज्यमन्त्री प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मन्त्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय, तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या: D.O. No. F.1/15/2010-IR दिनांक: 25 अगस्त 2010 (प्रति संलग्न है) के अनुपालन में आर०टी० आई० की गतिविधि से जुड़े "आवेदक विभूति नारायण दुबे, आर०टी० आई० कार्यकर्ता" की सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री व जिला मजिस्ट्रेट भदोही द्वारा आज दिनांक तक न किये जाने की स्थिति में "आवेदक के सुरक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में तथा भारत सरकार के उक्त आदेश का सम्बन्धित लोगों द्वारा अनुपालन न किये जाने की स्थिति में" मा० प्रधानमन्त्री भारत सरकार द्वारा आवश्यक उचित कार्यवाही करके कार्यवाही रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

(iv) अपेक्षित सूचना डाक द्वारा उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(v) डाक की दशा - पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा

(4) क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे का है - नहीं

स्थान - संसारपुर

संलग्नक-1. संदेय शुल्क रु० 10/- मूल्य का भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या: 25F 004624

2. मा० पृथ्वीराज चव्हाण महोदय राज्यमन्त्री भारत सरकार का आर० टी० आई० कार्यकर्ताओं की सुरक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में पत्र सं. D.O. No. F. 1/15/2010. IR दि० 25 अगस्त 2010 (छायाप्रति)

आवेदक का हस्ताक्षर

[signature]

03/03/14

(विभूति नारायण दुबे)

30

7

D.O.No. F.1/15/2010-IR

Prithviraj Chavan
ster of State (IC) for Science & Technology and Earth Sciences;
Minister of State in the Prime Minister's Office;
Personnel, Public Grievances and Pensions
and Parliamentary Affairs
Government of India, New Delhi

सत्यमेव जयते

पृथ्वीराज चव्हाण
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगीकी मंत्रालय;
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय;
राज्यमंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय तथा
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली

25 AUG 2010

Dear

As you are aware, Right to Information (RTI) was enacted in 2005 with the objective of improving transparency in the working of the Government and accountability of public servants. In a short span of 5 years, this Act has made a significant impact at both Central and State Government level. A large number of RTI requests are being filed regularly across the country and this is slowly but surely changing the way Governments function right up to the field level.

2. However, precisely because information is being sought and provided under the RTI Act on all the activities of Government bodies at various levels, and in many cases corruption and mal-administration has been exposed, disturbing reports have appeared recently in media about the victimization of people who use RTI (and PILs based on such information) to expose corruption and irregularities in administration. Media has also reported that during the last year, 8 activists have been allegedly murdered. There are also reports that information seekers are often threatened or physically intimidated. Civil Society Organizations have also highlighted this issue. Although, correct facts in all these cases would emerge only after proper investigations are made, if true this is a serious matter and cannot be allowed to continue, as it will negate the very purpose for which the Act was legislated.

3. The success of the RTI Act so far is due to the combined efforts of Central and State Governments and we need to take all steps to ensure that an atmosphere is created where citizens can exercise this right freely and without fear. State Governments have a crucial role to play in creating such an enabling environment.

4. There are enough provisions in the CrPC and IPC to enable the law enforcement machinery in your State to take strict preventive and punitive actions against such people who hinder the smooth

.....2/-

functioning of the Act. District Authorities need to be sensitized in this regard. At the State level, if any such instance comes to the notice, it should be promptly inquired into and action taken against the offenders. I understand that some States have taken steps to sensitise District authorities in this regard and have issued detailed instructions. You may also like to consider issuing similar instructions to District authorities in this respect.

With regards,

Yours sincerely,

Chief Ministers of all States/UT Administrator

(Prithviraj Chavan)